



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 548 राँची, मंगलवार, 27 अगस्त, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

1 अगस्त, 2024

संख्या-5/आरोप-1-517/2014-26662(HRMS)--मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड के गै०स०प्रे०सं०-3600171, दिनांक 29.08.2013 द्वारा दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" में दिनांक 10.08.2013 को प्रकाशित "आरक्षण का लाभ ले गये बाहरी" शीर्षक समाचार के कतरन की प्रति संलग्न करते हुए जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

2. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-10577, दिनांक 31.10.2013 द्वारा श्री प्रभात भूषण सिंह, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-236/20) से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (नियोजन हेतु) की माँग की गयी, किन्तु उनके द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराकर पत्र भेजने के आधार पर ही प्रश्न उठाया गया ।

3. श्री सिंह द्वारा गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पिछड़ी जाति के आरक्षण में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने संबंधी मामले की जाँच के क्रम में विभागीय पत्रांक-9702, दिनांक 05.11.2015 द्वारा उपायुक्त, धनबाद को श्री सिंह के प्रमाण पत्र भेजते हुए मंतव्य सहित जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई ।

4. उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-4130, दिनांक 08.12.2015 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराते हुए कहा गया कि श्री सिंह के प्रमाण पत्र का सत्यापन कार्यालय के संधारित पंजी से मिलान किया गया, जो पंजी के क्रमांक-783/05, दिनांक 23.09.2005 में इनका नाम दर्ज है, जाति का कुशवाहा (कोयरी) अंकित है। उपायुक्त, धनबाद से स्पष्ट मंतव्य अप्राप्त रहने पर पुनः विभागीय पत्रांक-729, दिनांक 29.01.2016 एवं स्मार पत्रों द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदन/मंतव्य की माँग की गयी।

5. उपायुक्त, धनबाद से श्री सिंह के प्रमाण पत्र पर स्पष्ट मंतव्य अप्राप्त रहने पर मामले की समीक्षोपरांत विभाग स्तर पर इनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप- श्री प्रभात भूषण सिंह, झा०प्र०से०, तृतीय बैच द्वारा केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए मान्य स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत तृतीय जे०पी०एस०सी० के द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्राप्त कर ली गई। श्री सिंह का यह कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल है एवं दण्डनीय है।

6. श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-6668, दिनांक 02.08.2016 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-56, दिनांक 16.02.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपी के विरुद्ध गठित आरोप "विधिसम्मत एवं उचित नहीं प्रतीत होता है" प्रतिवेदित किया गया है।

7. श्री सिंह के विरुद्ध आरोप, इनका बचाव बयान एवं जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरुद्ध सेवा से मुक्त/बर्खास्तगी की कार्रवाई की बिन्दु पर निर्णय लेने के पूर्व विधि विभाग, झारखण्ड से परामर्श की माँग की गई। विधि विभाग, झारखण्ड से प्राप्त परामर्श के उपरांत पुनः मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-5405, दिनांक 09.07.2019 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग से तृतीय संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित विज्ञापन एवं उक्त परीक्षा में वांछित स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र की माँग की गई। झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक-3738, दिनांक 22.12.2020 द्वारा संबंधित विज्ञापन एवं वांछित प्रमाण पत्रों का प्रपत्र उपलब्ध कराया गया। समीक्षोपरांत विधि विभाग, झारखण्ड से निम्न बिन्दु पर पुनः परामर्श की माँग की गई-

(क) आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०-17222, दिनांक 26.06.2010 झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन सं०-11/2007 के क्रम में स्वीकार्य है या नहीं।

(ख) विज्ञापन सं०-11/2007 के आलोक में आरोपी पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति के काफी वर्षों पश्चात् समर्पित स्थानीय प्रमाण पत्र सं०-8, दिनांक 05.08.2016 स्वीकार्य है या नहीं।

8. विधि विभाग, झारखण्ड के परामर्श का कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

"Thus in view of ambiguity in Para-10 of said advertisement as also in view of the fact that no objection was raised by Jharkhand Public Service Commission at relevant time and also subsequently no objection was raised by verifying authority as also in view of the fact that several persons have submitted identical certificates and have been declared successful and are working and further in the light of

Judgment of Hon'ble Supreme Court in the case of Pankaj Kumar, the issue cannot be reopened at this stage.

In the light of aforesaid facts and circumstances, in my opinion, the answer to the first query as to whether this certificate no. 17222 dated 26th June 2010 submitted by the petitioner which was valid only for the purpose of educational institutions can be accepted to be valid in terms of advertisement no 11/ 2007 is that it can be accepted as valid.

The answer to second query is that the certificate submitted by the delinquent being certificate no. 8 dated 05.08.2016 is not acceptable as the same has been issued in terms of resolution number 3198 dated 18th September 2016 which was not valid on the date of submission of application. The same can not be accepted as it has been submitted after expiry of date of submission and can not be considered in view of judgment of Hon'ble High Court reported in 2019 (1) JLJR 209 (HC)."

अतः विधि विभाग, झारखण्ड से प्राप्त परामर्श एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री प्रभात भूषण सिंह, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-236/20) को आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रभात भूषण सिंह, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PRABHAT BHUSHAN SINGH JHK/JAS/159	श्री प्रभात भूषण सिंह, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-236/20) को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
